

1857 के विद्रोह के परिणाम (विन्डुकार श्रेणी बद्ध)

- इसके बाद भारत में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। और ब्रिटिश राज ने भारत का शासन सीधे अपने हाथों में ले लिया था।
- इस विद्रोह के तुरन्त पश्चात् कम्पनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए गठित किए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ गवर्नेट्स नामक दोनों संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया था। तथा इनके स्थान पर एक भारतीय सचिव तथा उसकी 15 सदस्य इंडिया काउंसिल की स्थापना की गयी थी। (यह भारत सचिव ब्रिटिश सरकार का भारत सम्बन्धी मामलों देखने वाला एक मंत्री होता था।)
- इस विद्रोह के बाद एक भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था। इसके माध्यम से भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वाइसराय बना दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इस अधिनियम के पारित किये जाने के बाद लार्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था (और इसलिए लार्ड कैनिंग भारत का अन्तिम गवर्नर जनरल तथा भारत का वाइसराय बना था)।
- इस विद्रोह के बाद, ब्रिटिश शासन ने भारत में सम्राज्य विस्तार करने की नीति का त्याग कर दिया था तथा लोगों के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की नीति अपनाई थी।
- इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए एक पील आयोग गठित किया गया था। इस आयोग ने ब्रिटिश सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। उस रिपोर्ट के आधार पर भारतीय सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपिय सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया गया था।
- 1857 के विद्रोह के पश्चात् एक रॉयल आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने ब्रिटिश सरकार को सिफारीश की थी कि भारतीय सेना में अब जाति, समुदाय और धर्म इत्यादि के आधार पर रजिमेंटों का गठन किया जाना चाहिए और इसका अनुसरण करते हुए ब्रिटिश सरकार ने यही नीति अपनाई। इस नीति का मूल उद्देश्य समाज को विभाजित करना था और ऐसी ही नीतियों को "फूट डालो और राजनीति करो की नीति" कहा जाता है।